प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2012-13/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of grant of DR @ 65% from 01.10.2012 to judicial officers of Madhya Pradesh.
Ref:- 1. Special Seal Authority No PR1/Genl/SS/1828-1861 dt 26.10.2012 of the Accountant General (A&E) II Madhya Pradesh, Gwalior.

***

I am herewith enclosing a special seal authority received from the Accountant General, (A&E) II, Madhya Pradesh, Gwalior in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

L
474002 01.11.2012
757C 00106099

भारत INDIA POSTAGE
Rs 5.00
P670389

Under Spl. Seal Authority

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय O/o. Prl. A.G. (A&E) INWARD
06 NOV 2012
हैदराबाद-500 004. A.P. HYDERABAD-500 004.

PM

Spl. Seal

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II MADHYA PRADESH
GWALIOR (M.P.)

No. PRI/General/SS/ 1828-1861 Dated 26 .10.2012

The Principal Accountant General (A&E)
Andhra Pradesh,
Hyderabad - 500004

23654
7/11/12

Sub.: Regarding enhancement of Pension relief to Judges of Supreme Court and High Court Judges @ 58% w.e.f. 01.07.2011 and @65% w.e.f. 01.10.2012.

Ref: **Madhya Pradesh High Court, Jabalpur Letter No. C/9898/Do-1-3/53/Bhag-3-D dated 24.11.2011 and M.P. Govt. Law Deptt. Letter No. F.3(A)19/03/21-B(1) dated 04.2012.**

Sir,

Enclosed herewith Madhya Pradesh Judicial Officers relief Orders under reference regarding the above subject, and to state that instructions contained therein may be followed strictly. The entire pension disbursing banks in the district may be directed suitably .

VI

Encl: As above

Yours faithfully,

(signature)

Accounts Officer/PR

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

कमांक फा. 3(ए)19/03/21–ब(एक) भोपाल,दिनांक /04/2012

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर.

विषयः– मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2012 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत का भुगतान।

101503

केन्द्र सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भारत सरकार,कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेशंन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के ज्ञापन कमांक 42/13/2012–पी एंड पी डब्ल्यू (जी) दिनांक 04.04.2012 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दिनांक 01.01.2012 से पेंशन पर राहत 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राज्य शासन,मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन,पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 के नियम–11(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.01.2012 से पेंशन पर राहत 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार,कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेशंन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के ज्ञापन कमांक 42/13/2011–पी एंड पी डब्ल्यू (जी) दिनांक 04.04.2012 में बताई गई विधि से होगा।

(2) इस आदेश के तहत देय महंगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.01.2012 से नगद किया जावेगा।

(3 इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.डी.खान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II
O/o A.G. (A & E) II

......2......

No.L-11025/05/2011-Jus
Government of India
Ministry of Law and Justice
(Department of Justice)
****

Jaisalmer House, Mansingh Road,
New Delhi, the 17th April, 2012.

To

The Chief Secretaries,
All State Govts./UT of Delhi and Chandigarh,

Subject: Payment of Dearness Allowance to the Judges of Supreme Court and High Courts.

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 19th October, 2011 on the above subject and to say that the Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide O.M. No.1(1)/2012-E.II(B) dated 03.04.2012 (copy enclosed) has revised the rates of Dearness Allowance (D.A.) payable to Central Government employees w.e.f.1st January, 2012. As per the revised rates the Central Govt. employees are entitled to Dearness Allowance @ 65% (revised from 58% to 65%).

2. The revised rates of Dearness Allowance are also admissible to the Members of All India Services by virtue of the provisions contained in Rule 3 of the All India Service (D.A) Rules, 1972.

3. By virtue of the provisions contained in Rule 2 of High Court Judges Rules, 1956 and Rule 6 of the Supreme Court Judges Rules, 1959, the Judges of the High Courts and Supreme Court are also entitled to the revised rates of Dearness Allowance w.e.f.01.01.2012 at the same rates (65%) as are admissible to the members of All India Service. The admissibility of Dearness Allowance would be subject to other conditions as stipulated by D/o. Expenditure's above-mentioned O.M.

4. This issues with the concurrence of Integrated Finance Division vide Dy. No.418/12-B&A dated 12.04.2012.

Yours faithfully,

(Z.A. Khan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23382978.

कार्या. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II
O/o A.G. (A & E) II
7 MAY 2012
मध्य प्रदेश, ग्वालियर
Madhya Pradesh, Gwalior

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
2. The Registrar Generals, all High Courts.
3. The Pay and Accounts Office, Supreme Court of India, New Delhi.
4. The Pay and Accounts Office, No. XIV, Fire Station Building, Shanker Road, New Delhi.

.....2/-

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पत्र क्रमांक C/9898/
दो–1–3/53/भाग 3 डी

प्रेषक:– आर0पी0पाण्डेय,
रजिस्ट्रार,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
जबलपुर (म.प्र.)

प्रति,

महालेखाकार,
लेखा एवं हकदारी (द्वितीय),
मध्यप्रदेश झांसी रोड,
ग्वालियर (म0प्र0)

012571

जबलपुर, दिनांक 24/11/2011

विषयः– उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त माननीय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति/न्यायाधिपति महोदयों के पेंशन प्रकरणों में पेंशन पर 58 प्रतिशत की दर से राहत के भुगतान के संबंध में।

***

PR

महोदय,

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी ओर सचिव, भारत सरकार विधि तथा न्याय मंत्रालय न्याय विभाग, नई दिल्ली के पत्र एल– 19016/01/2011 –जस दिनांक 24–10–2011 एवं उसके सलग्न की छायाप्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त माननीय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति/न्यायाधिपति महोदयों के पेंशन प्रकरणों में पेंशन पर 58 प्रतिशत की दर से राहत के भुगतान के संबंध में संबंधित कोषालय अधिकारियों को अनुदेश जारी कर कृपया उसकी सूचना रजिस्ट्री को भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भ व दी य
23.11.11
(आर0पी0पाण्डेय)
रजिस्ट्रार

R-I
19/12

पृष्ठांकन क्रमांक C/9899/ जबलपुर, दिनांक 24/11/2011
दो–1–3/53/भाग 3 डी

प्रतिलिपिः– सहपत्र की छायाप्रति सहित प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर, ग्वालियर (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर0पी0पाण्डेय)
रजिस्ट्रार

S.S. 118
3/2/12

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कार्यालय महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी) द्वितीय
O/o A.G. (A & E) - II
29 NOV 2011
मध्य प्रदेश, ग्वालियर
Madhya Pradesh, Gwalior

Mamta